

प्रकाशन का 107 वाँ वर्ष

अजय

3 रूपये मात्र



लखनऊ, बुधवार 27 अक्टूबर, 2026 | Online Edition : www.ajhindidaily.com | नगर संस्करण पृष्ठ-12 | मूल्य 3.00 रुपये

वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, (मध्य प्रदेश संस्करण), कानपुर, (झांसी संस्करण), लखनऊ , आगरा, बरेली, पटना, रांची, (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित

सपा-कांग्रेस ने विकास में रोड़े अटकाये-मुख्यमंत्री

कहा-छोटे मियां-बड़े मियांको घुसपैठियोंसे प्यार



कानपुर (आससे.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक समारोह के दौरान अपने भाषण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया पर इशारों-इशारों दोनों को छोटे मियां और बड़े मियां कहते हुए सियासी हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि इस समय देश में दो मियां है-छोटे मियां और बड़े मियां। दोनों को घुसपैठियों से प्यार है। कानपुर बिठुर में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि आश्रम में पूजा-अर्चना के बाद नाना राव पेशवा पार्क में 411 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसी समारोह में उन्होंने अपने संबोधन में राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा।

अयोध्या को फिर से त्रेता युग की ओरले जायेंगे-योगी

अयोध्या (आससे.)। अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ-साथ अयोध्या को फिर से त्रेता युग की ओर ले कर के जाएंगे। मथुरा, वृंदावन फिर से नए भव्य और दिव्य रूप में, प्रयागराज भव्य और दिव्यमहाकुंभ के रूप में मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर हो, शुकतीर्थ हो, नैमिषारण्य का विकास हो, बिठूर का विकास हो, ये सभी तो आगे बढ़ेंगे ही। हमारी सरकार ने तय किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सदुरु रविदास जी महाराज, भगवान महर्षि वाल्मीकि से जितने भी स्थल प्रदेश में हैं उनकी बाउंड्री वाल करना अगर ऊपर से छाजन नहीं है तो उसमें कैनोपी की व्यवस्था करके छत की व्यवस्था करना, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के साथ-साथ सुंदरीकरण करने के लिए ऐसे 4,000 स्थानों पर यह कार्य वर्तमान में प्रारंभ होने वाला है।

'शिकायत है तो अदालत जाएं, अपना पक्ष रख सकते हैं'

नयी दिल्ली (आससे.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर शिकायत करने वाले विपक्षी दल न्याय पाने के लिए अदालतों का रुख कर सकते हैं और वहां अपना पक्ष रख सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में विपक्षी दलों के लगातार प्रदर्शन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कार्रवाई की मांग के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि देशभर से मिली शिकायतों को अदालतों ने संज्ञान में लिया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा, लोग अदालती कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं और अदालतों के माध्यम से न्याय पा सकते हैं। कई लोग पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। सीतारमण ने आगे कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों के जरिए भी इस मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में स्ट्रक्र को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

पार्किंग विवाद में अंधाधुंध फायरिंग, तीन की मौत



आरोपी मौके से पिस्टल सहित गिरफ्तार

लखनऊ। सआदतगंज के नौबस्ता स्थित ब्राह्मणी टोला में पार्किंग के विवाद में सोमवार को शिवाजी तिवारी (60), उनके भाई शंभू तिवारी (55) और बेटे सुयश तिवारी (30) की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। पड़ोस में रहने वाले 30 वर्षीय ऋषभ शुक्ला ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी और उसकी तीन बहनों को गिरफ्तार कर ऋषभ के पास से अवैध पिस्टल और चार खोखे बरामद किए। दोनों पक्षों में बरगद के पेड़ का चबूतरा बनाने को लेकर भी लंबे समय से विवाद है। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के मुताबिक बरगद के पेड़ के पास खाली पड़ी जमीन पर कार खड़ी करने को लेकर सुबह 10.30 बजे दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसी दौरान पड़ोसी दिनेश शुक्ला के बेटे ऋषभ ने अवैध पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से शिवाजी, शंभू और सुयश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस तीनों को केजीएमयू लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शंभू की पत्नी रुचि तिवारी की तहरीर पर आरोपी ऋषभ शुक्ला, उसके पिता दिनेश शुक्ला, चाचा राजेश शुक्ला, गिरीश शुक्ला और बहन प्रीति, अदिति व दिव्या के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सआदतगंज के नौबस्ता क्षेत्र में एक बरगद के पेड़ के आगे चबूतरा बनाने और वाहन पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी. बरगद के पेड़ के आगे चबूतरा बनाने को लेकर शिवा तिवारी उनके भाई शम्भू तिवारी और शिवा के बेटे सुयश तिवारी और उनके पड़ोसी के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी पक्ष ने असलहा निकालकर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गयी। फायरिंग की चपेट में आकर शिवा तिवारी, उनके भाई शम्भू तिवारी और शिवा के बेटे सुयश तिवारी लहूलुहान होकर गिर पड़े।आनन-फानन में पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे घायल की हालत नाजुक बनी थी. उसकी भी मौत हो गयी। परिजनों का कहना है कि सुयश का रिश्ता तय हो चुका था. परिवार के लोग काफी खुश थे. घर में शादी का माहौल बना हुआ था. उसकी शादी एक महीने बाद होनी थी, लेकिन ऋषभ ने उसकी हत्या कर दी.

100 करोड़ के स्कूल घोटाले मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री गिरफ्तार

चेन्नई (एजेंसी)। चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को कथित 100 करोड़ रुपये के स्कूल मान्यता घोटाले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता, स्कूलों का स्तर बढ़ाने की मंजूरी और अन्य जरूरी अनुमतियां दिलाने के नाम पर स्कूल प्रबंधन से 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वसूली गई। मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमवार को केंद्रीय अपराध शाखा की टीम ने चेन्नई स्थित उनके अपार्टमेंट से उन्हें गिरफ्तार किया।

यूपी विधान परिषद चुनाव की मतगणना आज

लखनऊ (आससे.)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक की पांच और शिक्षक की छह निर्वाचन सीटों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 की मतगणना मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में निर्धारित केंद्रों पर कराई जाएगी। लखनऊ-स्नातक सीट की मतगणना हॉल नंबर 7 और शिक्षक सीट की हॉल नंबर 8 में रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ में होगी। वाराणसी-स्नातक सीट की मतगणना हॉल नंबर 1 और शिक्षक सीट की हॉल नंबर 2 में स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन, वाराणसी में होगी।

फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं, एसआईआर पर फैसले सर्वसम्मति से-चुनाव आयोग

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब



नयी दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद तेज हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 15 बिंदुओं वाला जवाबी हलफनामा दाखिल कर अपनी प्रक्रिया और फैसलों का बचाव किया। आयोग ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए याचिका के आधार पर भी सवाल उठाए। आयोग का कहना है कि याचिका एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने इस हलफनामे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। यह मामला राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं की याचिका से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने, मतदाता सूची से हटाए गए नामों का स्वतंत्र ऑडिट कराने और बूथवार सूची उपलब्ध कराने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि किसी योग्य मतदाता का नाम बिना सूचना दिए और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जाना चाहिए। आयोग ने अपने जवाब में निर्णय लेने की प्रक्रिया, फॉर्म-6, मतदाता सूची और डिजिटल डेटाबेस को लेकर उठाए गए सवालों पर सफाई दी है। आयोग ने कहा कि जून 2025, अक्तूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर को लेकर जारी तीनों आदेश आयोग के सर्वसम्मत फैसले थे।

ज्ञानेश को हटायें, 30 सेकेंड में रोक देंगे आन्दोलन-राहुल

व्यापारियों की अपील के बावजूद एक नवम्बर को दिल्ली में कांग्रेस का होगा मार्च



नयी दिल्ली (आससे.)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित 'चलो दिल्ली मार्च' को जारी रखने के संकेत दिए हैं। उन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग करें। राहुल ने कहा कि ऐसा होने पर आंदोलन 30 सेकंड में रोक दिया जाएगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस व्यापारियों की चिंताओं को सुन रही है और उनसे प्यार करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मेट्रो बंद की, सड़कों को सील किया और राजधानी में आवाजाही बाधित की। उन्होंने दावा किया कि जब वोट ही चोरी हो जाएं, तो दुकान, बचत और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह जाता। यह मार्च मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस ने देशभर से कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। इसमें विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के अन्य दलों के भी शामिल होने की संभावना है। इससे पहले दिल्ली के व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर मार्च दीपावली के बाद आयोजित करने की अपील की थी। संगठन का कहना है कि एक नवंबर के आसपास धनतेरस, दीपावली और भैया दूज जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण बाजारों में भारी भीड़ रहती है। व्यापारियों के मुताबिक, रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली और कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख बाजार हैं।

त्योहारों के दौरान कारोबार प्रभावित होने की आशंका

मानहानि मामले में राहुल बरी

नयी दिल्ली (आससे.)। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत से मानहानि के एक मामले में बरी किए जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपराधियों के हाथों में चल रही है। कांग्रेस ने कहा कि वह महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते हुए प्यार, करुणा और धैर्य के साथ भाजपा को हराने की लड़ाई जारी रखेगी।राहुल गांधी को साल 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में सोमवार को बरी कर दिया गया। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे ने इसकी पुष्टि की। मामला सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में चल रहा था।

मोदी के पिता पर खरगे की टिप्पणी को लेकर भाजपा का देशव्यापी प्रदर्शन



नयी दिल्ली (आससे.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी को लेकर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ आज देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल, पटना में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में खरगे ने कहा कि मोदी का बाप भी जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक शख्स द्वारा यह कहे जाने पर पीएम मोदी कहीं जाएंगे, जवाब में गुस्से में आकर यह टिप्पणी की थी। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना बीजेपी का विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम शुरू। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पार्टी दफ्तर से निकले। इनकम टैक्स चौराहे तक विरोध प्रदर्शन किये। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत अपमान का रूप नहीं देना चाहिए। आज देशभर में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं।

2.12 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को सरकार की मंजूरी

नयी दिल्ली (आससे.)। सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को तीनों सेनाओं के लिए 2.12 लाख करोड़ की खरीद को मंजूरी दी। इसमें मल्टीपरपज हेलिकॉप्टर, लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन सिस्टम और हथियार शामिल हैं। इनमें करीब 82 प्रतिशत खरीदी भारतीय उद्योगों से की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे। नौसेना और वायुसेना के लिए भी कई अहम प्लेटफॉर्म, हेलिकॉप्टर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को मंजूरी मिली है। लाइट मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।

ज्ञानेश कुमार को बचाने में जुटी मोदी सरकार-खड़गे



नयी दिल्ली (आससे.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कथित वोट चोरी के मामलों के बावजूद मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर की जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगे जाने पर चुनाव आयोग ने 'ट्रेड सीक्रेट्स' का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म-6 के तहत आए 16.18 लाख आवेदनों का विवरण भी सार्वजनिक नहीं किया गया। खड़गे के मुताबिक, पीलीभीत में 10,470 मतदाताओं के रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की जांच के आदेश देने पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन की तीन प्रमुख मांगें हैं। पहली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और उन्हें संरक्षण देने वाला कानून निरस्त किया जाए।

अतीक अहमद की करोड़ों की 14 संपत्तियां कुर्क

प्रयागराज (एजेंसी)। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये के 14 भूखंड कुर्क कर लिए। ये भूखंड असदुल्लापुर भीटी में स्थित हैं। इनका कुल क्षेत्रफल करीब 11 बीघा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक, इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया था और इनकी रजिस्ट्री मदन लाल भारतीय के नाम पर कराई गई थी।पुलिस आयुक्त न्यायालय ने 27 जुलाई 2026 को इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। यह आदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में रविवार को कैंट थाना प्रभारी अमरनाथ राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान संपत्तियों पर कुर्की से संबंधित बोर्ड भी लगाए गए।

ब्रिक्स संसदें वैश्विक शांति में निभायें अहम भूमिका-बिरला



नयी दिल्ली (आससे.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि ब्रिक्स की सफलता केवल चर्चाओं से नहीं, बल्कि उनसे निकलने वाले ठोस परिणामों से तय होगी। उन्होंने सदस्य देशों की संसदों से जन-केंद्रित विकास, वैश्विक शांति और सतत विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। बिरला संसद भवन स्थित संविधान सदन में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच, 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से मंजूरी दिए जाने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अब साझा प्रतिबद्धताओं को ठोस नतीजों में बदलने की जरूरत है। कानून निर्माण, बजट और निगरानी के माध्यम से संसदें इसमें अहम भूमिका निभा सकती हैं।उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच संवाद, कूटनीति और सहयोग का महत्व बढ़ गया है। संसदें आपसी विश्वास मजबूत करने और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में प्रभावी योगदान दे सकती हैं।



समुद्र में भारत की नयी ताकत 'मातंगी'

बिना इंसान के 1500 किलोमीटर का सफर तय करने वाला स्वदेशी ऑटोनॉमस ड्रोन बोट



नयी दिल्ली (आससे.)। भारत रक्षा क्षेत्र में नेक्स्ट जेनरेशन तकनीक और स्वदेशी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में स्वदेशी तकनीक से विकसित 'मातंगी' ऑटोनॉमस सरफेस वेसल भारत की समुद्री क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित मातंगी एक ऐसा मानवरहित सतही पोत है, जो बिना किसी इंसान के सवार हुए समुद्र में लंबी दूरी तय करने में सक्षम है।वर्ष 2024 में इसने मुंबई से तमिलनाडु के तूतीकोरिन तक लगभग 1,500 किलोमीटर की यात्रा बिना मानवीय हस्तक्षेप के पूरी की थी। मातंगी में स्वायत्त नेविगेशन और टक्कर से बचने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी प्रणालियां समुद्र में पोत की दिशा निर्धारित करने, आसपास की परिस्थितियों को समझने और सुरक्षित संचालन में मदद कर सकती हैं। भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में मानवरहित प्रणालियों के विकास की दिशा में एक अहम पहल है 'वरुणा' ड्रोन। पुणे की कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित यह एक पायलटलेस एरियल व्हीकल है, जिसे एक व्यक्ति को लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के स्वावलंबन कार्यक्रम के दौरान वरुणा ड्रोन का प्रदर्शन देखा था। इस तकनीक ने भविष्य में मानव परिवहन के लिए मानवरहित हवाई प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की संभावनाओं को सामने रखा। 150 किलो तक पेलोड ले जाने की क्षमता/ वरुणा को एक व्यक्ति को हवा में ले जाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इसकी पेलोड क्षमता लगभग 150 किलोग्राम बताई गई है। इसमें ऑटोनॉमस टेक-ऑफ और लैंडिंग जैसी क्षमताएं भी शामिल हैं। समुद्र में युद्धपोतों के बीच जरूरी सामान पहुंचाना, आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता देना और भविष्य में मेडिकल इवैक्युएशन जैसे कार्य इस प्रकार की तकनीक के संभावित इस्तेमाल में शामिल हो सकते हैं। समुद्र में पारंपरिक

चक्रवात अर्नब आंध्र की तरफ बढ़ा, चार राज्यों में अलर्ट

नयी दिल्ली (आससे.)। सैटेलाइट तस्वीर में चक्रवात अर्नब के चारों ओर घने बादल और बीच में तूफान का केंद्र दिखाई दे रहा है। चक्रवात अर्नब बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह 27 अक्टूबर तक तूफान का रूप ले सकता है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 140 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।आंध्र प्रदेश में करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी है। तटीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया

महाराष्ट्र (एजेंसी)। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय ओका ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व जज ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। उन्होंने स्वतंत्र संस्थाओं की गरिमा की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी तंत्र और एक ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया। रविवार को ठाणे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अस (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हम) विषय पर आयोजित एक व्याख्यान में बोलते हुए, जस्टिस ओका (सेवानिवृत्त) ने उच्च-स्तरीय संवैधानिक नियुक्तियों में जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था और कानूनी प्रावधान बनाना जरूरी है।